

# हरियाणा में तीन चौथाई बहुमत से सरकार बनायेगी कांग्रेस: पायलट

सचिन पायलट ने कहा कि जनता ने भाजपा को बता दिया कि घमंड व अहंकार से राज नहीं कर सकते



कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट 30 सितंबर से हरियाणा के चुनाव प्रचार अभियान पर हैं। आज उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित किया। वे 2 और 3 अक्टूबर को भी हरियाणा में ही रहेंगे।

जयपुर, 1 अक्टूबर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। जनता ने कांग्रेस को विजयी बनाने का मन बना लिया है। जो लोग 300 पार, 400 पार का नारा लगाते थे, जनता ने उनकी नकारात्मक सोच और घमण्ड का जवाब देते हुए लोकसभा चुनावों में उन्हें बहुमत भी पार करने नहीं दिया। देश की जनता ने

भाजपा को आईना दिखाते हुए बता दिया कि आप घमण्ड और अहंकार से राज नहीं कर सकते, तानाशाही तरीके से राज नहीं कर सकते, आप लोगों की भावनाओं से खेलकर, मंदिर-मस्जिद की बात करके वोट नहीं ले सकते। पायलट 30 सितंबर व 1 अक्टूबर को हरियाणा के चुनावी दौरे पर रहे। अपने चुनावी कार्यक्रम के दौरान पायलट ने 30 सितंबर को हरियाणा के विधानसभा क्षेत्र भवानी

खेड़ा एवं फरीदाबाद एन.आई.टी. तथा 1 अक्टूबर को घरौड़ा, समालखा, नांगल चौधरी, हथीन तथा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। पायलट 2 अक्टूबर को हरियाणा के सोहना एवं जगाधरी तथा 3 अक्टूबर को महेन्द्रगढ़, तोशाम, बरवाला, पलवल विधानसभा क्षेत्रों के चुनावी दौरे पर रहेंगे।

कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने हरियाणा में भवानी खेड़ा, फरीदाबाद, घरौड़ा, समालखा, नांगल चौधरी, हथीन, बादशाहपुर में चुनावी सभाओं की वे दो और तीन को सोहना, जगाधरी, महेन्द्रगढ़, तोशाम, बरवाला, पलवल में चुनावी दौरा करेंगे।

सभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने देश और प्रदेश की भाजपा की सरकार के दस सालों के कुशासन को झेला है। किसानों को परेशान किया गया, उन पर लाठी-गोलियां चलायी गईं, सैकड़ों किसानों ने शहादत दी। भाजपा धर्म, जाति, मंदिर-मस्जिद की बातें करके वोट लेना जानती है। भाजपा का खाद, बिजली, पानी, सड़क, निवेश, विकास जैसे मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि भाजपा के दस सालों के कुशासन, भय, पक्षपात और भाई से भाई को लड़ाने की सोच, दमनकारी राजनीति का पुरजोर जवाब देते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें।

## पर्यावरण ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) करती है। भाजपा सोनम वांगचुक पर जो बल प्रयोग कर रही है, वह उसे गैंगस्टर्स पर करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर अहंकारी और अलोकतांत्रिक होने का आरोप लगाया और कहा, सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार ने शांतिपूर्ण मार्च कर रहे लड़ाखी लोगों को गिरफ्तार किया है। खड़गे ने कहा कि वांगचुक की मांगों को जनता का समर्थन है। मोदी सरकार अपने करीबी उद्योगपतियों की खातिर लड़ाख के हिमालयी ग्लेशियर्स, जो पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील हैं, का दोहन करना चाहती है। कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने इस घटना का संबंध महात्मा गांधी के विचारों से जोड़ा। उन्होंने कहा, गांधी जयंती से पहले भारत सरकार एक बार फिर गांधी के विचारों की हत्या कर रही है। वांगचुक जी की गिरफ्तारी से स्पष्ट होता है कि सरकार हर उस व्यक्ति से डरती है, जो अपने अधिकारों के लिए बोलता है। उन्होंने भाजपा पर लड़ाख की जनता का मुंह बंद कर यह क्षेत्र अपने कारपोरेट मित्रों को देने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसी कारपोरेट हस्तक्षेपों के रास्ते पर चलने वालों को नहीं रोक सकता है। यह पहली बार नहीं है, जब वांगचुक ने लड़ाख की तरफ लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश की है। मार्च में उन्होंने लड़ाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और उद्योगों द्वारा लड़ाख के संवेदनशील लैंड स्केप के दोहन के खिलाफ 21 दिन का उपवास किया था।

## 200 भारतीय ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) के पब्लिक स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षकों से सहायक होंगे, उनका भाषा-कोशल साझा करेंगे तथा फ्रांसीसी विद्यार्थियों से जुड़ेंगे। यह अनुभव उन्हें फ्रांसीसी भाषा एवं संस्कृति को समझने तथा वहाँ के लोगों के निकट रहते हुये काम करने का अवसर प्रदान करेगा। फ्रांस जाने वाले इन शिक्षकों के लिये, आई.बी.आई.एस. होटल एयरोसिटी, नई दिल्ली में एक प्री-डिपार्चर सत्र आयोजित किया गया, जहाँ ग्रीगोआर टुमेल, जो आई.एफ.आई. के निदेशक तथा नई दिल्ली स्थित फ्रांसीसी दूतावास में को-ऑपरेशन एण्ड कल्चरल अफेयर्स के काउन्सलर हैं, ने विदेश जाने से पहले अक्सिस्टेंट्स से बातचीत की। "द फ्रेंच इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडिया" के निदेशक ग्रीगोआर टुमेल ने

कहा, "लैंग्वेज अक्सिस्टेंट प्रोग्राम हमारे दोनों देशों को नजदीक लाता है। लैंग्वेज अक्सिस्टेंट्स फ्रांस में भारतीय संस्कृति तथा भारत में फ्रांसीसी संस्कृति के विशिष्ट अधिकार प्राप्त राजदूत होते हैं। फ्रांसीसी युवाओं के साथ फ्रांसीसी शिक्षा व्यवस्था में कार्य करके, वे पारस्परिक सांस्कृतिक सुदृढ़ीकरण में एक रणनीतिक भूमिका निभाते हैं, जो सर्वोत्कृष्ट द्विपक्षीय फ्रांस-भारत संबंधों की मुख्य चाबी है। इस वर्ष इस प्रोग्राम के लिये 206 भारतीय भाषा सहायकों का चयन हुआ है। इनके अलावा इनके साथ, 61 वापस लौटने वाले अक्सिस्टेंट्स होंगे, जिन्होंने फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ अपने अनुबंधों का नवीनीकरण करा लिया है। ये अक्सिस्टेंट्स फ्रांस के विभिन्न शैक्षिक विभागों में काम करेंगे, जिन्हें "एकेडमीज" कहा जाता है।

## जमैका के प्रधानमंत्री का भारत में स्वागत

नई दिल्ली, 01 अक्टूबर। जमैका के प्रधानमंत्री होलेनेस भारत यात्रा पर हैं। पीएम मोदी ने मंगलवार को होलेनेस और उनके देश से आए प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। इस दौरान जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलेनेस और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में भारत और जमैका के बीच समझौता ज्ञापन भी आदान-प्रदान किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि जमैका भारत का लंबे समय से मित्र रहा है। प्रधानमंत्री होलेनेस से कई बार मिलने

■ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि 180 साल पहले भारत से आपसी संबंधों की मजबूत नींव रखी थी।

का अवसर मिला है और हर बार मैंने भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को महसूस किया है। मुझे विश्वास है कि उनकी यात्रा हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ पूरे कैरेबियाई क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ऊर्जा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जमैका के संबंध हमारे साझा इतिहास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित है। भारत और जमैका के बीच व्यापार और निवेश बढ़ रहा है। भारत हमेशा जमैका की विकास यात्रा में एक विश्वसनीय और प्रतिबद्ध विकास भागीदार रहा है।

## 'दूसरे राज्यों से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) मौजूद थे, और उन्होंने अदालत के समक्ष स्वीकार किया कि एफ.एस.एल. और डी.एन.ए. रिपोर्ट समय पर तैयार करने के लिए पर्याप्त संसाधन मुहैया कराना राज्य सरकार का दायित्व है।

इस संबंध में वर्ष 2014 से हाईकोर्ट निरंतर आदेश पारित कर रहा है, लेकिन आदेशों की पालना नहीं हो रही है। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2019 से वर्षवार लंबित मामलों का रिकॉर्ड भी पेश किया गया, जिसमें सामने आया कि लंबित मामलों छह साल में 3136 से बढ़कर 20 हजार से अधिक हो गए हैं।

अदालत ने अधिकारियों को कहा कि गंभीर मामलों में यदि आरोपी को जमानत दी जाती है तो पीड़ित पक्ष के साथ अन्याय हो सकता है। वहाँ, राज्य सरकार की निष्क्रियता के कारण आरोपी को अकारण जेल में रखा जाता है तो उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है। प्रकरण 13 साल की बालिका से दुष्कर्म से जुड़ा है, लेकिन सरकार की संवेदनशीलता प्रकट नहीं हुई है। अदालत ने सरकार से जवाब मांगा कि अदालत यह विकल्प क्यों न अपनाए कि रिपोर्ट में देरी के चलते सरकार पर हर्जाना लगाकर राशि आरोपी को दी जाए।

## कई दशकों के इंतज़ार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) लोग "सिंकिंग फीलिंग" कहते हैं, वैसी स्थिति थी।

जापान की सभी समस्याओं को जड़ वहाँ की जनसंख्या में लगातार कमी आना है। हालाँकि यह स्थिति अकेले जापान की ही नहीं है। विकसित विश्व के अधिकांश देश जनसंख्या के कम होते जाने की समस्या का सामना कर रहे हैं, लेकिन जापान में यह समस्या कुछ ज्यादा ही विकट है। जनसंख्या के कम होने से गाँव वीरान हो गये हैं, पढ़ने वाले छोटे बच्चों के अभाव में किन्डरगार्टन स्कूल बंद हो गये हैं तथा फैक्ट्रियों को और कारीगर नहीं मिल रहे हैं।

जापान द्वारा आप्रवासन (बाहर से आकर बस जाना) की अनुमति नहीं दिये जाने के कारण, जापान की हालत खराब हो गई है। जापान की जनसंख्या में जापान मूल के लोग ही दिखाई दे रहे हैं। अब आकर, जब जनसंख्या कम होते जाने का दबाव बहुत विकट हो गया है, जापान कुछ

विदेशियों को यहाँ आकर बसने की अनुमति देने लगा है। कुछ लोग पड़ोसी देश चीन से जापान में पहुँच रहे हैं। लेकिन इनकी संख्या बहुत ही कम है तथा इनका आना भी किसी भी समय रूक सकता है क्योंकि चीन स्वयं भी जनसंख्या में कमी की समस्या का सामना कर रहा है।


वस्तुतः कोई भी नई सरकार जनसंख्या की प्रवृत्ति (ट्रेंड) को उलट तो नहीं सकती। जनसंख्या ट्रेन्ड बहुत लम्बी अवधि के बाद ही बदल पाते हैं। लेकिन नीतियों के बदलने से कुछ राहत जरूर मिलती है। इसके अलावा, जापान की स्थिति इसलिये भी नहीं उलट सकती, क्योंकि वहाँ की करीब 30 प्रतिशत जनसंख्या 60 वर्ष से ऊपर की है। उनकी पैशन तथा चिकित्सा सुविधा में समाज की आय का एक अच्छा-खासा हिस्सा काम आ जाता है।

लेकिन और अधिक राहत युक्त आप्रवासन नीति काम करने वाले हाथों की कमी को कम कर सकती

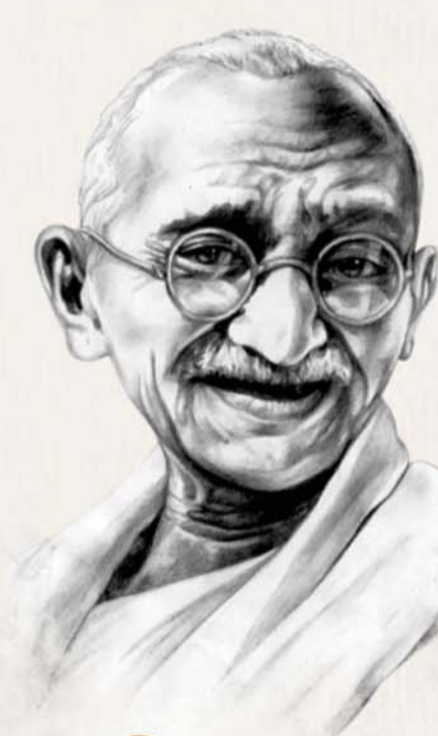

है। इसके अलावा, जापान को महिलाओं के प्रति अपनी सोच एवं रवैया बदलना होगा, जो अभी भी जबरदस्त भेदभाव का सामना कर रही हैं। काम में महिलाओं की बड़े पैमाने पर भागीदारी से कुछ राहत की स्थिति बन सकती है। लेकिन हाल ही की कुछ सरकारें महिलाओं की प्रजनन-संबंधी भूमिका के राग अलापी रही हैं।

और ज्यादा दबाव बना रहे आर्थिक मुद्दों में शामिल एक मुद्दा है-कीमती की स्थिरता, जिसका उल्लेख पहले हो चुका है। कीमती अधिकांशतः तो कम ही हुई है और अगर बढ़ी भी है तो वर्ष में करीब 0.3 प्रतिशत मात्र।

इस जबरदस्त सुस्ती एवं मंदी के विरुद्ध, "बैन ऑफ जापान" ने अपना महँगाई लक्ष्य 2 प्रतिशत रखा था। मॉग को प्रोत्साहित करके, कीमतों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, सेंट्रल बैंक ने अपनी ब्याज दर कम कर दी थी।



राजस्थान सरकार



# राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी

व पूर्व प्रधानमंत्री

# लाल बहादुर शास्त्री जी

की जयंती पर शत-शत नमन

2 अक्टूबर 2024

श्री नरेन्द्र मोदी  
माननीय प्रधानमंत्री

श्री भजनलाल शर्मा  
माननीय मन्त्री

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

## मुख्यमंत्री ने कॉन्क्लेव को राज्य के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों में हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया (कॉन्कोर), एनटीपीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईआरडीए, पीजीसीआईएल, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी, सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन (आईटीडीसी), फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई), न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल), राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई-एमएसएमई), आईआरसीटीसी, एग्रिकल्चर रिकल कार्डसिल ऑफ इंडिया (एएससीआई), ऑटोमोटिव रिकल्स डेवलपमेंट कार्डसिल, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), एफआईसीएसआई (खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए सेक्टर रिकल कार्डसिल), मैनेजमेंट एंड ऑटोमेटिज़ेशन एंड प्रोफेशनल रिकल्स कार्डसिल (एमएपीएससी) शामिल हैं। राजस्थान सरकार को आगामी

■ हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के चेयरमैन, भारत इलैक्ट्रॉनिक्स के सी.एम.डी., कॉन्कोर के सी.एम.डी. ने राजस्थान सरकार के साथ काम करने के सुखद अनुभव बताये।

ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए शुभकामना देते हुए हिंदुस्तान पेट्रोलियम के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रजनीश नारंग ने कहा कि राज्य सरकार ने हमें हर स्तर पर महत्वपूर्ण और त्वरित समर्थन दिया है। रिफाइनरी की न केवल वर्तमान जरूरतों के लिए, बल्कि भविष्य के इसके संभावित विस्तार के लिए भी भूमि का आवंटन सरकार द्वारा शीघ्रता से किया गया।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज जैन ने कहा, देश के डिफेंस मैनुफैक्चरिंग के क्षेत्र में राजस्थान एक बड़े औद्योगिक राज्य के रूप में उभर रहा है। कॉन्कोर के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय स्वरूप ने एलएनजी (लिविंगफाइंड नेचुरल गैस) जैसे परिवहन के टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल साधनों के विस्तार की

आवश्यकता के बारे में बताया और लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने में राजस्थान सरकार द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की।

इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि, राजस्थान में अक्षय ऊर्जा, डिफेंस मैनुफैक्चरिंग, पेट्रोकेमिकल्स और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएँ हैं। हमारे पास जमीन की कमी नहीं है, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अपार क्षमता है, प्रचुर खनिज भंडार हैं और कुशल कार्यबल है।

इनके जरिए हम राज्य और सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों - दोनों के लिए साझा समृद्धि सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ मिलकर हम सब 'विकसित भारत' और 'विकसित राजस्थान' के लक्ष्य को साकार कर सकते हैं।

इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राजवर्धन राठौड़ ने कहा,

इस कॉन्क्लेव में भाग लेने वाले सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज राजस्थान की अध्यक्षता में अगले पांच वर्षों में दोगुना करके 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने के राज्य सरकार के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

इस अवसर पर मुख्य सचिव सुधाश पंत ने कहा, राज्य में काम कर रहे सी.पी.एस.ई.ज का आधार मैं राज्य सरकार की ओर से व्यक्त करता हूँ क्योंकि राज्य की समृद्धि और विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। 'राजिंज राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 निजी क्षेत्र और सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पी.एस.ई.) से निवेश आकर्षित करने पर समान रूप से जोर देता है।

इस अवसर पर एक प्रेजेंटेशन देते हुए उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताम शर्मा ने कहा कि दिल्ली से नजदीक होने की वजह से राजस्थान एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएँ हैं जिसका फायदा राज्य में निवेश करके केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज उठा सकती है।